



# उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

## मुंबई में मानसून का रौद्र रूप: तीन की मौत पर उठे सवाल, स्कूल-कॉलेज बंद; फ्लाइट्स ठप-अलर्ट पर प्रशासन

मुंबई, 05 जुलाई। मानसून की बारिश मुंबई के लिए आफत बनकर आई है। रविवार को मुंबई में भारी बारिश और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई, जिससे हवाई यात्रा बाधित हुई, तीन व्यक्ति की मौत हो गई और शहर में मानसून की तैयारियों को लेकर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई।

देश की आर्थिक राजधानी के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 200 से 300 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई। मरीन ड्राइव व गेटवे ऑफ इंडिया के पास ऊंची लहरें देखी गईं। शहर के अलग-अलग हिस्सों से आई तस्वीरों में समुद्र का उग्र रूप दिखाई दिया, जबकि लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित होता रहा।

मुंबई में मौसम विभाग के ऑरेंज

अलर्ट के मद्देनजर सोमवार को सभी सरकारी एवं निजी स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। रातभर हुई भारी बारिश के कारण रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे का संचालन एक घंटे के लिए रोकना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे का कामकाज लगभग एक घंटे के लिए बंद होने से फ्लाइट्स संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ, जबकि क्टरुने और तेज बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुबह 10.17 बजे से 11.17 बजे के बीच रनवे का कामकाज रोकना पड़ा, जिससे आने और जाने



वाली दोनों तरह की फ्लाइट्स बाधित हुईं।

खराब मौसम के कारण इंडिगो की चार फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं और अलग-अलग एयरलाइंस की 13 आने वाली फ्लाइट्स का रास्ता बदलना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक, हालात सुधरने के बाद रास्ता बदली गई सभी फ्लाइट्स मुंबई लौट गईं और सुरक्षित उतर गईं।

मुंबई में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई। कुर्ला वेस्ट के कमानी इलाके में गोम्स गाउन बिल्डिंग के पास हिंदी बोएम्सी स्कूल के पास एक दुकान पर पेड़ गिरने से 63 वर्षीय युवक कुड़ावाला की मौत हो

गई। यह घटना दोपहर करीब 12:40 बजे हुई। मुंबई के कुर्ला में रविवार को भारी बारिश के दौरान एक दुकान पर पेड़ गिरने से 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के गोरगांव में टक्करोड पर एक केमिस्ट की दुकान के बाहर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे दो महिलाएं उसके नीचे दब गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह घटना उज्ज्वर में कैद हो गई।

पेड़ गिरते ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और पेड़ के नीचे फंसी दोनों महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश की। जल्द ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 15 मिनट में पेड़ को हटा दिया गया, जिससे सड़क पर ट्रैफिक फिर से शुरू हो सका।

## बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर भारत सरकार का कड़ा रुख, इंस्टाग्राम-मेटा को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 05 जुलाई। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा को एक बहुत ही सख्त नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इंस्टाग्राम पर पेड़ विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर दिया गया है।

सरकार ने इंस्टाग्राम को आदेश दिया है कि वह ऐसे सभी विज्ञापनों और कंटेंट को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटाए जो इस तरह की गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही सरकार ने कंपनी से 7 दिनों के भीतर इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी के साथ जवाब मांगा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे थे जो यूजर्स को क्लिक करने पर दूसरे बाहरी प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स पर ले जाते थे। उन बाहरी प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े इस गैर-कानूनी



आपत्तिजनक और गैर-कानूनी कंटेंट मौजूद था। सरकार इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही है, क्योंकि आरोप है कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के जरिए ही ऐसे खतरनाक कंटेंट को बढ़ावा मिल रहा था। शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका सरकार ने मेटा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह बच्चों के शोषण से जुड़े इस गैर-कानूनी

मटीरियल के प्रचार और फैलाव को रोकने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को फैलाने और लोगों तक इसकी पहुंच आसान बनाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।

## मानसून की रफ्तार: दिल्ली-यूपी-राजस्थान समेत उत्तर भारत में झमाझम बारिश; 11 जुलाई तक का अलर्ट

नई दिल्ली, 05 जुलाई। देश के अलग-अलग राज्यों बारिश के दौरा शुरू हो गया है। दिल्ली कई हिस्सों में 5-20 मिमी प्रति घंटे की रफ्तार से मध्यम से भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शहादरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में हवा की गति 40-50 किमी घंटा रहने और इसके 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है।

IMD के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 6 जुलाई और 10 जुलाई को कहीं-कहीं बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि, 7 से 9 जुलाई के बीच और फिर 11 जुलाई को बारिश का दायरा बढ़कर काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके तक फैल सकता है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में 6-9 जुलाई और 11 जुलाई को दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। राजस्थान में मानसून की गतिविधियां तेज होने वाली हैं। IMD



ने पूर्वी राजस्थान में 6 जुलाई से 10 जुलाई तक बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है और यह 11 जुलाई को भी जारी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। पूरे सप्ताह दोनों क्षेत्रों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40-60 किमी प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी रहेगा।

## राम मंदिर मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला

लखनऊ, 05 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को राम मंदिर के मुद्दे को लेकर निशाना साधते हुए विपक्ष पर हिंदू आस्था का अपमान और मंदिर आंदोलन का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी को भी भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नवीन ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की 'साइकिल कबाड़खाने में भेज दी जाएगी'।

उन्होंने जोर देकर कहा कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा को 2047 तक चुनाव जीतते रहना होगा। विपक्षी दलों के नेताओं को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में वित्तीय अनियमितता मामले में चुनौती देते हुए नवीन ने कहा कि हिंदू धर्म को

इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झंसे में आ जाएंगे। नितिन नवीन ने यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अवध क्षेत्र के शक्ति केन्द्र संयोजकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जी हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झंसे में आएंगे, आपके भरमाने में आयेगे।

उन्होंने आरोप लगाया, "हमने देखा है कि जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देखा गया है कि जब राम चरित मानस का अपमान हुआ तो कांग्रेस के लोग मौन बैठे थे। नवीन ने कहा, "आज कुछ लोग अयोध्या के श्रीराम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्रीराम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। इन लोगों ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया कि प्रभु

श्रीराम एक कल्पित काल्पनिक चीज हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थीं और अयोध्या की पवित्र नगरी पर खून की नदियां बहाने थीं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज वे लोग आस्था की बात करते हैं, ये हमारा खून भी बह जाएगा तो हम इस बात की चिंता करेंगे कि प्रभु श्रीराम की आस्था से कोई खेल नहीं सकता, चाहे कितनी भी कुबानी देनी पड़े। नवीन ने कहा कि भाजपा सरकार ने



(आरएसएस) और विहिप का संघर्ष और 500 वर्षों का आस्था का जो संघर्ष है, वह कहीं न कहीं अयोध्या के भक्तों और श्रीराम मंदिर के रूप में सामने दिखाता है। नवीन ने कहा, "मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारा खून भी बह जाएगा तो हम इस बात की चिंता करेंगे कि प्रभु श्रीराम की आस्था से कोई खेल नहीं सकता, चाहे कितनी भी कुबानी देनी पड़े। नवीन ने कहा कि भाजपा सरकार ने

स्पष्ट किया है कि हर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "आपने तो खून की नदियां बहाई हैं, आपकी विरासत हिंदुओं पर गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत देवी देवताओं की आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है।" नवीन ने कहा, "हमने विरासत को संजोया है, उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे।" नितिन नवीन ने कहा कि शक्ति केन्द्र संयोजकों के बल पर 2027 में फिर से भाजपा का कमल खिलने को तैयार है। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारत की आत्मा बसती है और उस उग्र में जहां पर प्रभु श्रीराम का जन्म का हुआ हो, वहां मयारदा पुरुषोत्तम हमारा आदर्श ही नहीं हम सबको दिशा देते हैं। इस भूमि ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिसने देश ही नहीं दुनिया को रास्ता दिया है।

## अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली, 05 जुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल, 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र पारदर्शिता, तकनीक के उपयोग, संस्थागत सुदृढीकरण और जमीनी स्तर के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा है। पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी बैंकों, डेयरी सहकारी समितियों, शहरी सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं और बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए कई परिवर्तनकारी पहलों की हैं। इस अवसर पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय



मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री; भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान; कृष्ण पाल गुर्जर, सहकारिता राज्य मंत्री; और मुरलीधर मोहोले, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ-साथ, इस अवसर पर डॉ. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय; आतिश चंद्र, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; और नरेश पाल गंगवार, सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

## गांवों के विकास को नई उड़ान, 'वीबी-जी-राम-जी' योजना के तहत केंद्र ने जारी किए 25863 करोड़ रुपये की पहली किस्त

नई दिल्ली, 05 जुलाई। केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 'विकसित

भारत- गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी-जी-राम-जी' योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 25,863 करोड़ की भारी-भरकम राशि जारी कर दी है। सरकार का संकल्प है कि इस योजना के जरिये ग्रामीणों को सम्मानजनक रोजगार मिले और उनके पसीने की हर बूंद का सही मोल समय पर चुकाया जा सके।



केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस राशि का उद्देश्य राज्यों के पास पर्याप्त फंड सुनिश्चित करना है ताकि ग्रामियों को 15 दिनों के भीतर उनकी मजदूरी मिल सके। उन्होंने राज्यों से अपना हिस्सा भी समय पर जारी करने की अपील की। ग्रामीण भाई-बहनों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए इस योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब देश के किसी भी राज्य में दैनिक मजदूरी 300 से कम नहीं होगी।

जहां पुरानी 'मनरेगा' योजना को पूरे देश में लागू होने में करीब तीन साल लग गए थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'वीबी-जी-राम-जी' को एक जुलाई से पूरे देश में एक ही दिन में लागू कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, केरलम और राजस्थान ने पहले ही दिन बड़े पैमाने पर रोजगार देकर शानदार मिसाल पेश की है।

**TIWARI'S SARASWATI CLASSES**  
— Since 1992 —  
Parents' First Choice for 34+ Years  
Prof. Dr. Dayanand Tiwari  
Founder & Academic Director

**ADMISSIONS OPEN**  
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE  
NEET | JEE | MHT-CET  
10 DAYS FREE DEMO  
Attend Classes • Experience Our Teaching  
Take Admission After Satisfaction  
(No Hidden Conditions)

- ✓ 34+ Years of Academic Excellence
- ✓ Experienced & Dedicated Faculty
- ✓ Personal Attention
- ✓ Printed Notes & Regular Tests
- ✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams

📍 Santacruz Branch  
101 Sai Chambers,  
Opp. Santacruz Railway Station (East),  
Near Depot, Santacruz (E), Mumbai 400055

📍 Sion Branch  
Opp. SIES College (Old),  
Near Gaurahiga Hotel,  
Sion (West), Mumbai

Limited Seats / Small Batch Size  
CALL NOW:  
**7738007373**

**DAKS REHAB CENTRE**  
(PARALYSIS PHYSIOTHERAPY CENTER AND OLD AGE HOME)

**Contact us: 9820519851**

विल्डिंग नंबर 3, फ्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीवी नगर मुंबई-37

- \* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
- \* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
- \* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
- \* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
- \* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
- \* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
- \* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
- \* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
- \* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
- \* विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
- \* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तियों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

**NEW LIGHT CLASSES**  
TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheetal Bldg.  
Near Dianond Talkies,  
L. T. Road, Borivali (West)  
Mumbai - 400 092  
Maharashtra

**ADMISSIONS OPEN**  
ALL OVER INDIA  
**ENROLL NOW**

**SMART CLASSROOM**

(ONLINE/OFFLINE)  
**Courses Offered**

- Std. XI & XII (Sci.)
- MHT-CET
- NEET
- Polytechnic & Engg
- JEE (Main & Advance)
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

## विकास की धंसती सड़कें और भ्रष्टाचार की गहरी नींवें



-ललित गर्ग

जिस दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को आधुनिक भारत के तेज, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी सड़क उद्घाटन के महज ढाई महीने बाद पहली ही बरसात में धंस गई। सड़क इस तरह धंसी कि कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सीमाय से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया। प्रश्न यह है कि करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क पहली ही वर्षा का सामना क्यों नहीं कर सकी? क्या निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया? क्या जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं थी? या फिर यह भ्रष्टाचार, लापरवाही और जवाबदेही के अभाव का परिणाम है? यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में नई सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों और सार्वजनिक भवनों के ध्वस्त होने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे-बड़े पुलों का गिर जाना पूरे देश को झकझोर गया था। एक ही दिन पांच पुल-पुलियों का धराशायी होना केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का जीवंत प्रमाण था। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई। कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर के गिरने से अनेक परिवार उजड़ गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 की छत गिरने की घटना और मुंबई के घाटकोपर में विशाल हॉर्डिंग गिरने से



अशोक भाटिया

चरित्र और प्रभाव में जमीन-आसमान का अंतर है। ग्रामीण बाढ़ मुख्य रूप से नदियों के जलस्तर बढ़ने या उनके तटबंध टूटने से मैदानी इलाकों में धीरे-धीरे फैलती है। इसके विपरीत, शहरी बाढ़ एक अत्यधिक केंद्रित, तीव्र और 'मानव-निर्मित' आपदा है। शहरीकरण के कारण कंक्रीट की अभेद्य सतहों का निर्माण होता है, जिससे जलभराव की गति सामान्य से 1.8 से 8 गुना तक बढ़ जाती है और पानी की मात्रा में 6 गुना तक की वृद्धि देखी जाती है। शहरों में घनी आबादी और अरबों रूपयों का बुनियादी ढांचा दांव पर होता है। चंद्र घंटों की मूसलाधार बारिश पूरे शहर के परिवहन, बिजली ग्रिड, इंटरनेट संचार और स्वास्थ्य सेवाओं को घुटनों पर ला देती है। शहरी बाढ़ के कारणों को केवल 'प्रकृति का प्रकोप' कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे अनियोजित विकास और प्रशासनिक लापरवाही की एक लंबी कतार है। शहरों के पास जो तालाब, झीलें और दलदली भूमि थीं, वे प्राकृतिक 'स्पंज' या बफर का काम करती थीं, जो अतिरिक्त वर्षा जल को सोख लेती थीं। लेकिन रियल एस्टेट और अनियोजित शहरी विस्तार की भूख ने इन जल निकायों को निगल लिया है। उदाहरण के लिए, बंगलुरु ने पिछले कुछ दशकों में अपने अंतर्संबंधित झीलों के तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंक्रीट की इमारतों के कारण खो दिया है। चेन्नई और हैदराबाद में भी बाढ़ के मैदानों पर बहुमंजिला इमारतें और मॉल खड़े कर दिए गए हैं, जिससे पानी के बहने और ठहरने का प्राकृतिक रास्ता ही बंद हो गया है। भारत के अधिकांश महानगर आज भी दशकों पुराने, और मुंबई

जैसे शहर तो औपनिवेशिक काल के ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर हैं। यह बुनियादी ढांचा उस समय की आबादी और वर्षा के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मिसाल के तौर पर, मुंबई का पुराना ड्रेनेज सिस्टम प्रति घंटे अधिकतम 25 मिमी बारिश का पानी निकालने की क्षमता रखता था, जबकि आज जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में प्रति घंटे 100 मिमी से अधिक की अति-तीव्र बारिश हो रही है। इस बड़ी हुई क्षमता को संभालने में हमारे शहरों की संकरी और गाद से भरी नाली प्रणालियाँ पूरी तरह अक्षम हैं। विकास के नाम पर मिट्टी की जगह डामर और कंक्रीट ने ले ली है और वे विस्थापित होने पर मजबूर हो जाते हैं। महामारियाँ और स्वास्थ्य संकट: बाढ़ का गंदा पानी जब पीने के पानी की लाइनों में मिल जाता है, तो हैजा, टायफाइड, डेंगू, मेलरिया और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैलता है? अब समय 'रिफ्लेक्ट' (आपदा आने पर जागना) रवे को छोड़कर 'प्रोएक्टिव' (पहले से तैयारी) एडिक्टिव अपनाने का है। इसके लिए निम्नलिखित बहु-स्तरीय समाधानों को युद्धस्तर पर लागू करना होगा। जैसे 'स्पंज सिटी' की अवधारणा को अपनाना। आज चीन और कई यूरोपीय देशों की तर्ज पर भारतीय शहरों को 'स्पंज' में बदलना होगा। इसका अर्थ है कि शहर की रूपरेखा ऐसी हो जो वर्षा जल को बहने देने की बजाय खुद में सोख ले। इसके लिए-शहरों में पारगम्य कंक्रीट और ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाए जिसके नीचे पानी जमीन में जा सके। शहरी वनीकरण पार्कों और 'रिन गार्डन्स' को बढ़ावा दिया जाए ताकि हरी-भरी सतहें पानी के वेग

को कम कर सकें। 'ब्लू' (जल निकाय जैसे झील, तालाब, नदियाँ) और 'ग्रीन' (पार्क, पेड़-पौधे) के समन्वय से ही शहरों को बचाया जा सकता है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में इस अवधारणा को शामिल किया गया है। चेन्नई नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत झीलों के निर्माणों की पहल एक सराहेनीय उदाहरण है, जहाँ गाद निकालकर तालाबों की जल संचयन क्षमता को बढ़ाया गया है। इस मॉडल को देशव्यापी बनाना होगा। शहरी स्थानीय निकायों को आने वाले 50 वर्षों के वर्षा अनुमानों और जलवायु परिवर्तन के आंकड़ों के आधार पर अपने ड्रेनेज सिस्टम को रीडिजाइन करना चाहिए। नालियों की केवल मानसून से पहले सफाई नहीं, बल्कि चौबीसों घंटे निगरानी होनी चाहिए। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पंचायती राज मंत्रालय संगठन के मानकों के अनुसार ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार अनिवार्य किया जाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक सूचना प्रणाली और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर की मदद से जलभराव वाले हॉटस्पॉट की रियल-टाइम मैपिंग की जानी चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 'मौसम ऐप' और स्थानीय अलर्ट सिस्टम को इतना सटीक होना चाहिए कि भारी बारिश से दो घंटे पहले ही निचले इलाकों के नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके या यातायात को डायवर्ट किया जा सके। इसके अलावा, अंडरपास और सबवे में पानी भरने से रोकने के लिए आधुनिक 'इन्फ्लेटेबल फ्लड बैरियर्स' जैसी तकनीकों का त्वरित उपयोग किया जाना चाहिए। इसके के मैदानों और प्राकृतिक नालों पर निर्माण को पूरी तरह 'नो-

कंस्ट्रक्शन जेन' घोषित कर कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सरकार की अटफण्ड 210 योजना के तहत बरसाती नालों को जल निकायों से जोड़ने और 'मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज' के तहत 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) को अनिवार्य बनाने के नियम को कड़ाई से जमीन पर लागू करना होगा। शहरी बाढ़ अब केवल एक प्रशासनिक समस्या या इंजीनियरिंग की खामी नहीं है; यह हमारे विकास के प्रतिमानों पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। कंक्रीट के बेतरतीब जंगल खड़े करके हम खुद को 'वैश्विक महाशक्ति' या 'स्मार्ट' नहीं कह सकते, यदि हमारी अर्थव्यवस्था और जनजीवन चरण घटते की बारिश भी न झेल सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2010 में ही शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन वे आज भी नगर निगमों की पाइलों में धूल फांक रहे हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय के बिना इस संकट से पार पाना असंभव है यदि हम चाहते हैं कि हमारे शहर देश की आर्थिक प्रगति के इंजन बने रहें, तो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। पानी अपना रास्ता खुद ढूँढ लेता है; यदि हम उसे उसका रास्ता नहीं देंगे, तो वह हमारे घरों, दफ्तरों और तरककी के रास्तों में घुसकर सब कुछ तबाह करता रहेगा। समय आ गया है कि हम हबाद-लचीले शहरी नियोजन को अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं, अन्यथा हर साल मानसून का आगमन उत्पन्न की जगह एक त्रासदी बनकर आता रहेगा।



उत्तर प्रदेश में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में धंसा, वीडियो वायरल

हुई मौतों ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता गंभीर संकट से गुजर रही है।

इन घटनाओं को केवल प्राकृतिक आपदा या भारी वर्षा का परिणाम बताकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। यदि पहली ही बारिश में सड़क धंस जाए, पुल बह जाए या भवनों की छतें गिर जाएं, तो यह प्रकृति की नहीं, बल्कि मानव निर्मित विफलता की एवं गहरे में पड़े भ्रष्टाचार की कहानी है। आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक के इस युग में ऐसी घटनाएँ असंभव हैं। यह विकास नहीं, बल्कि विकास के नाम पर जनता के साथ किया गया विश्वासघात है। सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति की धमनियाँ होते हैं। इनके माध्यम से व्यापार चलता है, गांव शहरों से जुड़ते हैं, किसान अपने उपज बाजार तक पहुँचते हैं और आम नागरिक सुरक्षित आवागमन करते हैं। जब यही आधारभूत संरचनाएं असमय ध्वस्त होने लगें, तो केवल कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं टूटता, बल्कि जनता का शासन और प्रशासन पर विश्वास भी टूटता है।

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क धंसने के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर को निलंबित किया तथा निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल निलंबन से समस्या का समाधान हो जाएगा? अनुभव बताता है कि अधिकांश मामलों में निलंबित अधिकारी कुछ समय बाद बहाल हो जाते हैं या उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। जिन कंपनियों को काली सूची में डाला जाता है, वे कुछ समय बाद नए नाम से फिर सरकारी ठेके प्राप्त करने लगती हैं। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का चक्र लगातार चलता रहता है। वास्तविक समस्या जवाबदेही के अभाव की है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया-डिजाइन, सामग्री, तकनीकी परीक्षण और गुणवत्ता निंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं होती। जब दोषियों को कठोर दंड नहीं मिलता, तब भ्रष्टाचार की अप्रत्यक्ष संरक्षण मिल जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष बरसात के साथ सड़कें उखड़ती हैं, पुलों में दरारें पड़ती हैं और करोड़ों रुपये की परियोजनाएँ समय से पहले दम टोड़ देती हैं।

देश में सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। ठेके हासिल करने से लेकर बिलों के भुगतान तक अनेक स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब परियोजना की लागत का बड़ा भाग अवैध लेन-देन में खर्च हो जाता है, तब निर्माण की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। घंटिया सामग्री का उपयोग, तकनीकी मानकों की अनदेखी और समय सीमा का दबाव मिलकर ऐसी सरकारी तैयार करते हैं जो पहली ही परीक्षा में असफल हो जाती हैं। विडंबना यह भी है कि प्रत्येक दुर्घटना के बाद जांच समितियाँ गठित होती हैं, रिपोर्ट तैयार होती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आता। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं। जनता का आक्रोश धीरे-धीरे शांत हो जाता है और फिर कोई नई दुर्घटना उसी कहानी को दोहरा देती है। विकसित देशों में भी दुर्घटनाएँ होती हैं, किंतु वहाँ प्रत्येक हादसे के बाद प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं। भारत में सुधार की अपेक्षा लोभापोती अधिक दिखाई देती है।

अब समय आ गया है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। प्रत्येक परियोजना के लिए स्वतंत्र थर्ड-पार्टी गुणवत्ता ऑडिट अनिवार्य किया जाए। निर्माण सामग्री की डिजिटल ट्रैकिंग, प्रत्येक चरण का तकनीकी सत्यापन तथा ड्रेन और आधुनिक सेंसर आधारित निरीक्षण को व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। परियोजना पूरी होने के बाद केवल उद्घाटन नहीं, बल्कि निश्चित अवधि तक उसके प्रदर्शन का भी वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि दोषी अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों को व्यक्तिगत एवं आर्थिक जवाबदेही तय हो। यदि उनकी लापरवाही से जनहानि होती है या सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है, तो केवल निलंबन नहीं, बल्कि सेवा से बर्खास्तगी, आर्थिक दंड और आपराधिक मुकदमे जैसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।

भारत आज विकास राफ्ट बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे, आर्थिक गलियारे, हाई-स्पीड रेल, आधुनिक हवाई अड्डे और स्मार्ट शहर सभी सार्थक होंगे, जब उनकी नींव ईमानदारी, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर आधारित होगी। विकास का अर्थ केवल नई परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि उनका वर्षों तक सुरक्षित और टिकाऊ बने रहना भी है। आज आवश्यकता केवल नई सड़कें और पुल बनाने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें कोई भी सड़क पहली बारिश में न धंसे, कोई पुल उद्घाटन से पहले न गिरे और कोई हवाई अड्डा यात्रियों के लिए खतरा न बने। भ्रष्टाचार की गहरी नींव पर विकास की मजबूत इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है, तो विकास की चमक के साथ उसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। तभी जनता का विश्वास बचेगा, सार्वजनिक धन सुरक्षित रहेगा और विकास का मार्ग सचमुच मजबूत एवं स्थायी बन सकेगा।

## डूबते शहर, ठहरती जिन्दगी और खोखला विकास

जैसे शहर तो औपनिवेशिक काल के ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर हैं। यह बुनियादी ढांचा उस समय की आबादी और वर्षा के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मिसाल के तौर पर, मुंबई का पुराना ड्रेनेज सिस्टम प्रति घंटे अधिकतम 25 मिमी बारिश का पानी निकालने की क्षमता रखता था, जबकि आज जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में प्रति घंटे 100 मिमी से अधिक की अति-तीव्र बारिश हो रही है। इस बड़ी हुई क्षमता को संभालने में हमारे शहरों की संकरी और गाद से भरी नाली प्रणालियाँ पूरी तरह अक्षम हैं। विकास के नाम पर मिट्टी की जगह डामर और कंक्रीट ने ले ली है और वे विस्थापित होने पर मजबूर हो जाते हैं। महामारियाँ और स्वास्थ्य संकट: बाढ़ का गंदा पानी जब पीने के पानी की लाइनों में मिल जाता है, तो हैजा, टायफाइड, डेंगू, मेलरिया और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैलता है? अब समय 'रिफ्लेक्ट' (आपदा आने पर जागना) रवे को छोड़कर 'प्रोएक्टिव' (पहले से तैयारी) एडिक्टिव अपनाने का है। इसके लिए निम्नलिखित बहु-स्तरीय समाधानों को युद्धस्तर पर लागू करना होगा। जैसे 'स्पंज सिटी' की अवधारणा को अपनाना। आज चीन और कई यूरोपीय देशों की तर्ज पर भारतीय शहरों को 'स्पंज' में बदलना होगा। इसका अर्थ है कि शहर की रूपरेखा ऐसी हो जो वर्षा जल को बहने देने की बजाय खुद में सोख ले। इसके लिए-शहरों में पारगम्य कंक्रीट और ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाए जिसके नीचे पानी जमीन में जा सके। शहरी वनीकरण पार्कों और 'रिन गार्डन्स' को बढ़ावा दिया जाए ताकि हरी-भरी सतहें पानी के वेग

को कम कर सकें। 'ब्लू' (जल निकाय जैसे झील, तालाब, नदियाँ) और 'ग्रीन' (पार्क, पेड़-पौधे) के समन्वय से ही शहरों को बचाया जा सकता है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में इस अवधारणा को शामिल किया गया है। चेन्नई नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत झीलों के निर्माणों की पहल एक सराहेनीय उदाहरण है, जहाँ गाद निकालकर तालाबों की जल संचयन क्षमता को बढ़ाया गया है। इस मॉडल को देशव्यापी बनाना होगा। शहरी स्थानीय निकायों को आने वाले 50 वर्षों के वर्षा अनुमानों और जलवायु परिवर्तन के आंकड़ों के आधार पर अपने ड्रेनेज सिस्टम को रीडिजाइन करना चाहिए। नालियों की केवल मानसून से पहले सफाई नहीं, बल्कि चौबीसों घंटे निगरानी होनी चाहिए। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पंचायती राज मंत्रालय संगठन के मानकों के अनुसार ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार अनिवार्य किया जाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक सूचना प्रणाली और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर की मदद से जलभराव वाले हॉटस्पॉट की रियल-टाइम मैपिंग की जानी चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 'मौसम ऐप' और स्थानीय अलर्ट सिस्टम को इतना सटीक होना चाहिए कि भारी बारिश से दो घंटे पहले ही निचले इलाकों के नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके या यातायात को डायवर्ट किया जा सके। इसके अलावा, अंडरपास और सबवे में पानी भरने से रोकने के लिए आधुनिक 'इन्फ्लेटेबल फ्लड बैरियर्स' जैसी तकनीकों का त्वरित उपयोग किया जाना चाहिए। इसके के मैदानों और प्राकृतिक नालों पर निर्माण को पूरी तरह 'नो-

कंस्ट्रक्शन जेन' घोषित कर कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सरकार की अटफण्ड 210 योजना के तहत बरसाती नालों को जल निकायों से जोड़ने और 'मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज' के तहत 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) को अनिवार्य बनाने के नियम को कड़ाई से जमीन पर लागू करना होगा। शहरी बाढ़ अब केवल एक प्रशासनिक समस्या या इंजीनियरिंग की खामी नहीं है; यह हमारे विकास के प्रतिमानों पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। कंक्रीट के बेतरतीब जंगल खड़े करके हम खुद को 'वैश्विक महाशक्ति' या 'स्मार्ट' नहीं कह सकते, यदि हमारी अर्थव्यवस्था और जनजीवन चरण घटते की बारिश भी न झेल सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2010 में ही शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन वे आज भी नगर निगमों की पाइलों में धूल फांक रहे हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय के बिना इस संकट से पार पाना असंभव है यदि हम चाहते हैं कि हमारे शहर देश की आर्थिक प्रगति के इंजन बने रहें, तो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। पानी अपना रास्ता खुद ढूँढ लेता है; यदि हम उसे उसका रास्ता नहीं देंगे, तो वह हमारे घरों, दफ्तरों और तरककी के रास्तों में घुसकर सब कुछ तबाह करता रहेगा। समय आ गया है कि हम हबाद-लचीले शहरी नियोजन को अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं, अन्यथा हर साल मानसून का आगमन उत्पन्न की जगह एक त्रासदी बनकर आता रहेगा।

हुई मौतों ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता गंभीर संकट से गुजर रही है।

## चीन का नया कानून दुनिया में बहस का बड़ा मुद्दा

शी जिनिपिंग की सरकार ने 'झोंगहुआ मिन्सू' यानी एकीकृत चीनी राष्ट्र की अवधारणा को सबसे ऊपर रखा है। अब उसी सोच को पहली बार एक व्यापक राष्ट्रीय कानून का रूप दे दिया गया है। दरअसल यह कहानी आज से नहीं बल्कि कई दशक पहले शुरू हुई थी। 1984 में चीन ने रीजनल एथनिक ऑटोनॉमी लॉ बनाया था, जिसके तहत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अपनी भाषा और संस्कृति बचाने के कुछ अधिकार मिले थे। लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदलनी शुरू हुई। शी जिनिपिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और अलगाववाद को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए नई नीति अपनाई। शिनजियांग में निगरानी व्यवस्था बढ़ाई गई, तिब्बत में शिक्षा व्यवस्था बदली गई, इनर मंगोलिया में स्थानीय भाषा की जगह मंदारिन को बढ़ावा दिया गया। उस समय इन फैसलों का विरोध हुआ, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। अब वही सारी नीतियाँ एक नए कानून के जरिए स्थायी ढांचे में बदल गई हैं। इस कानून का सबसे बड़ा आधार भाषा है। चीन चाहता है कि पूरे देश में एक साझा भाषा के रूप में मंदारिन ही प्रमुख रहे। प्री-स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा का मुख्य माध्यम मंदारिन होगा। सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों और आधिकारिक संचार में भी इसी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि



-अजय कुमार

साझा भाषा आर्थिक अवसर बढ़ाती है, रोजगार आसान बनाती है और राष्ट्रीय एकता मजबूत करती है। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि पहचान का सबसे बड़ा आधार होती है। यदि किसी समुदाय की मातृभाषा धीरे-धीरे स्कूलों और सरकारी व्यवस्था से बाहर हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों में उसकी सांस्कृतिक पहचान भी कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि सबसे ज्यादा चिंता उद्गर, तिब्बती और मंगोल समुदायों को लेकर जताई जा रही है। शिनजियांग में करीब 1.2 करोड़ उद्गर मुसलमान, तिब्बत में लाखों तिब्बती बौद्ध और इनर मंगोलिया में बड़ी संख्या में मंगोल समुदाय रहता है। पिछले कुछ वर्षों से इन इलाकों में स्थानीय भाषाओं की जगह मंदारिन को बढ़ावा देने की नीति लागू की जा रही थी। अब नया कानून इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी सुरक्षा देता है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे आने वाले वर्षों

में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग केवल घरों तक सीमित रह सकता है। कानून केवल भाषा तक सीमित नहीं है। इसमें स्कूलों, परिवारों, मीडिया, सामाजिक संगठनों और सरकारी संस्थाओं को 'चीनी राष्ट्रीय पहचान' मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। पाठ्यक्रमों में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता और शी जिनिपिंग की विचारधारा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की बात भी सामने आई है ताकि अलग-अलग समुदायों के बीच सामाजिक दूरी कम हो। चीन इसे सामाजिक समरसता बना रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह विविधता को खत्म कर एक जैसी पहचान बनाने की कोशिश है। सबसे ज्यादा विवाद आर्टिकल-63 को लेकर है। यह प्रावधान कहता है कि यदि कोई चीनी नागरिक विदेश में रहकर भी चीन की जातीय एकता के खिलाफ गतिविधि करता है या अलगाववाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कानून का प्रभाव केवल चीन की सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रावधान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विदेशों में रहने वाले उद्गर, तिब्बती और अन्य कार्यकर्ताओं को भी इस कानून के अंतर्गत निशाना बनाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार

प्रमुख ने भी इस कानून पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि भाषा, धर्म, संस्कृति और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति पर अतिरिक्त नियंत्रण लगाया गया तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन हो सकता है। दूसरी ओर चीन इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। बीजिंग का कहना है कि यह कानून केवल आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ है तथा इसका उद्देश्य सभी जातीय समूहों को समान अवसर देना है। चीन लगातार दावा करता रहा है कि शिनजियांग और तिब्बत में उसकी नीतियों से गरीबी कम हुई है, शिक्षा बढ़ी है और आर्थिक विकास तेज हुआ है। असल सवाल यह है कि क्या यह कानून वास्तव में राष्ट्रीय एकता लाएगा या सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करेगा। इतिहास बताता है कि किसी भी देश में साझा राष्ट्रीय पहचान बनाया आसान नहीं होता। भाषा, संस्कृति और परंपरा लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है। जब सरकारें इन्हें बदलने की कोशिश करती हैं तो अवसर राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा होता है। चीन का कहना है कि उसकी प्राथमिकता स्थिरता और विकास है, जबकि आलोचकों का मानना है कि स्थिरता के नाम पर सांस्कृतिक विविधता को सीमित किया जा रहा है। भारत में चल रही यूनियनों सिविल कोड की बहस और चीन के इस कानून की तुलना भी इसी वजह से चर्चा में है।

लेकिन दोनों की प्रकृति पूरी तरह अलग है। भारत में यूसीसी का संबंध विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सिविल कानूनों से है। इसके विपरीत चीन का नया कानून भाषा, शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोनों को एक जैसा कानून कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। फिलहाल इतना तय है कि चीन ने केवल नया कानून लागू नहीं किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय नीति को नया कानूनी आधार दे दिया है। आने वाले वर्षों में इस कानून का असर केवल चीन तक सीमित नहीं रहेगा। विदेशों में रहने वाले चीनी मूल के लोगों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं और दुनिया की बड़ी लोकतांत्रिक सरकारों की नजर भी इसके हर कदम पर रहेगी। यदि यह कानून सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक असहमति के दायरे तक पहुँचा तो चीन और पश्चिमी देशों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। लेकिन अगर बीजिंग इसे केवल आतंकवाद और अलगाववाद तक सीमित रखने में सफल रहा तो वह इसे अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में शामिल करेगा। फिलहाल दुनिया इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि यह कानून राष्ट्रीय एकता का नया मॉडल बनेगा या सांस्कृतिक पहचान पर सबसे बड़ा कानूनी नियंत्रण साबित होगा।

## खामेनेई का अंतिम संस्कार: शोक आमंत्रण में छिपा है बड़ा सियासी संदेश

ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के निधन के बाद चार जुलाई 2026 को उनके अंतिम संस्कार को लेकर उपजे कूटनीतिक घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति और विदेश नीति के गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ईरान सरकार द्वारा भारत की कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों को इस शोक सभा में आमंत्रित करना न केवल दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों का संकेत है, बल्कि यह पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीति में भारत की बढ़ती अहमियत को भी रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला निमंत्रण इस बात का प्रमाण है कि ईरान भारत को अपने रणनीतिक भागीदारों की सूची में शीर्ष पर रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्थान पर बिहार के राज्यपाल को भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भेजना यह दशात है कि भारत कूटनीतिक शिष्टाचार और आंतरिक व्यवस्ताओं के बीच एक संतुलित रुख अपना रहा है। यह आमंत्रण भारत के लिए एक जटिल स्थिति भी पैदा करता है। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को बुलावा जाना यह स्पष्ट करता है कि ईरान भारत के किसी एक धड़े या सरकार से नहीं, बल्कि पूरे भारतीय तंत्र

की जटिलताओं को उजागर करता है। जब भारत सरकार के प्रतिनिधि आधिकारिक तौर पर ईरान के इस शोक आयोजन में शामिल होते हैं, तो वे अनजाने में ही घरेलू राजनीति में मौजूद समरोंह के लिए संकारात्मक संदेश देते हैं, जो ईरान के शीर्ष नेतृत्व के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। यह कदम भारत की उस स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी (रणनीतिक स्वायत्तता) को भी पुष्ट करता है, जहाँ भारत अमेरिका और इजरायल जैसे अपने अन्य रणनीतिक सहयोगियों के साथ संबंधों को प्रभावित किए बिना ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा का व्यापक प्रभाव यह होगा कि यह भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण राजनयिक घटना है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था, जो दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों का संकेत है। हालांकि, प्रधानमंत्री के पास पहले से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के चलते भारत सरकार ने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें बिहार के राज्यपाल लेपिनेट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हमसेन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मंगेरिता शामिल हैं। इस आमंत्रण की सबसे दिलचस्प कड़ी यह सूची है, जिसमें मुख्यधारा के कई राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। रिपोट्स के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मणिशंकर अहिर, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्रशीद और पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन

खेड़ा को निमंत्रण मिला है। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तथा जम्मू-कश्मीर के पाँच शिया धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किए जाने की खबरें हैं। ईरान की इस रणनीति के पीछे कई गहरे भू-राजनीतिक निहितार्थ छिपे हैं। सबसे स्पष्ट संदेश यह है कि ईरान भारत के साथ केवल सत्ताधारी दल के साथ ही नहीं, बल्कि भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और विविध राजनीतिक स्पेक्ट्रम के साथ अनुभवा जुड़ाव बनाए रखना चाहता है। विपक्षी नेताओं को भी क्षेत्रीय दिग्गजों को बुलाकर ईरान यह जनाना चाहता है कि उसका भारत से संबंध किसी एक सरकार या कार्यकाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ह्यूमन-से-ह्यूमन का रिश्ता है जो दशकों पुराना है। उद्गर, कई बड़े राजनीतिक चर्चों और रसूखदार नेताओं की आमंत्रण न मिलना ईरान की एक सधी हुई कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान नहीं चाहता कि इस गंभीर शोक आयोजन को किसी प्रकार की घरेलू राजनीतिक खिंचतान या अंतरराष्ट्रीय विवादों में घसीटा जाए। निमंत्रण सूची को बेहद चुनिंदा रखना यह भी बताता है

कि तेहरान भारत के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाने में बहुत सतर्क है। खेर, ऐसा लगता है कि यह पूरा घटनाक्रम भारत की उस स्थिति को और अधिक जातिल कर रहा है, जहाँ उसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ आगे बढ़ना होता है। एक तरफ चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के जरिए भारत ईरान के साथ अपने आर्थिक हित सुरक्षित करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसे अमेरिका और इजरायल के साथ अपने संबंधों का भी संतुलन बनाए रखना है। ईरान का यह आमंत्रण भारत की मल्टी-अलायमेंट नीति को एक बड़ी परीक्षा है। कुल मिलाकर, यह कूटनीतिक प्रतिनिधित्व सिर्फ एक अंतिम संस्कार में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह बदलते प्रतिनिधित्व सिर्फ एक अंतिम संस्कार में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की उस बैलेंसिंग एक्ट की एक कड़ी है, जो उसे एक साथ कई धुवों के साथ संबंध बनाए रखने की अनुमति देती है। आने वाले समय में यह दुनिया दिलचस्प होगा कि यह यात्रा ईरान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक और उर्जा सुरक्षा समझौतों को किस तरह नई गति देती है और क्या इसका असर भारत के भीतर रहे बने वाले ईरान समर्थक समुदाय को राजनीतिक सक्रियता पर कोई बड़ा प्रभाव डालेगा।







## इंदौर के रेती मंडी ब्रिज पर राजेंद्र नगर की ओर ट्रैफिक शुरू



प्रणित नरेंद्र तिवारी इंदौर (उत्तरशक्ति)। एबी रोड पर राजेंद्र नगर क्षेत्र में बन रहे रेती मंडी रेलवे ओवर ब्रिज को आखिरकार राऊ चौराहे से राजेंद्र नगर की तरफ आने वाले वाहनों के लिए खोल दिया गया है। ब्रिज का एक हिस्सा शुरू होने से प्रतिदिन सफर करने वाले

सैकड़ों वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की झंझट से बड़ी राहत मिली है हालांकि, दूसरी तरफ राऊ की ओर जाने वाले वाहनों को अब भी नीचे बनी सर्विस रोड से ही गुजरना पड़ रहा है। बारिश के इस मौसम में सर्विस रोड पर कीचड़ और गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

## एल.टी. मार्ग के सीनियर पीआई विजय दंडवते का हुआ सम्मान



मुंबई। एल.टी. मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर (पीआई) विजय दंडवते को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनेक समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस समारोह में वरिष्ठ समाजसेवी हीराला प्रसाद गुप्ता, समाजसेवक एवं कल्याण जिला कोषाध्यक्ष संजय तिवारी, नेता, ह्यकदम कदम परल्लहिंदी न्यूज पेपर के संपादक छोटे लाल शर्मा तथा केकेपी न्यूज के पत्रकार शिवा जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

उपस्थित लोगों ने विजय दंडवते के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें समाज और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का माहौल सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण रहा।

## कांग्रेस सभासद शहनवाज मंजूर के जन्मदिन पर उमड़ा बधाईयों का तांता



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर शहर कांग्रेस पार्टी के सभासद शहनवाज मंजूर के जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन को कामना करते हुए कहा कि शहनवाज मंजूर जनसेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर विभिन्न स्थानों से बधाई संदेश लगातार मिलते रहे, जिससे पूरा माहौल उत्सवपूर्ण बना रहा। मोहम्मद आरिफ खान शहर कांग्रेस अध्यक्ष, सत्य वीर सिंह अधिवक्ता, आदि

## ठगी व मारपीट के मामले में छह आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। ए.पी. कुंवर अनुपम सिंह के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पैसा दोगुना करने का दण्ड ठगी व मारने-पीटने के 6 नामजद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्र के अजोरपुर गांव निवासी विनय राय ने ए.पी.को प्रार्थना पत्र दिया देखकर आरोप लगाया कि गांव के विजय कुमार राय, गौरव ने भाई संतोष कुमार राय, देवी प्रसाद राय, सुख सागर राय व देवेन्द्र राय ने शीघ्र रुप दोगुना करने का झांसा देकर उनसे केटीएम से 40 हजार रुपए जमा कराए। केवल 10 हजार की रसीद दी। शेष 30 हजार मांगने पर टाल-मटोल करते रहे। दबाव बनाने पर 21 जून को गांलियां दले हुए आरोपीयों ने लाठी डंडा से मारा पीटा। और जान से मार डालने की धमकी दी। यूपी- 112 पर सूचना व कोतवाली में प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन पुलिस कर रही है।

## बिना फिटनेस और अधूरे कागजात पर दौड़ रहे स्कूली वाहन बच्चों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

केराकत जौनपुर (उत्तरशक्ति)। क्षेत्र में संचालित कुछ निजी विद्यालयों के वाहनों को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई स्कूलों में बच्चों के आवागमन के लिए ऐसे वाहन लगाए गए हैं जिनकी फिटनेस, परमिट, बीमा तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज अद्यतन नहीं हैं। कुछ वाहन जर्जर हालत में होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल वाहन बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। यदि बिना फिटनेस या नियमों के विपरीत वाहन संचालित हो रहे हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने जिला प्रशासन एवं आरटीओ विभाग से मांग की है कि क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों के वाहनों का विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण कराया जाए। जिन वाहनों के पास वैध फिटनेस, परमिट, बीमा या अन्य आवश्यक दस्तावेज न हों अथवा जो सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरते हों, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

## गोदान एक्सप्रेस के सामने कूदकर नौवीं की छात्रा ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस

मडियाहू, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कोतवाली क्षेत्र के मडियाहू बजारादर रेलवे ट्रैक पर रघुनाथपुर गांव के पास रविवार को एक 15 वर्षीय किशोरी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस स्टेशन में मडियाहू कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। मुंबई से छपरा जा रही गोदान एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 11059) के सामने रेलवे ट्रैक के किलोमीटर 33/11 पर किशोरी ने छलांग लगा दी। ट्रेन को चुपके में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान मुकुंदपुर गांव निवासी शिवबाबू पटेल की 15 वर्षीय पुत्री सोहाना के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। किशोरी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है तथा सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

## नितिश तिवारी को रुस में एमबीबीएस की डीग्री मिलने पर लोगों ने दी बधाई



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर उत्तर प्रदेश के डिहरीवा गावरी नगर निवासी सुबेदार तिवारी के नाती नितिश तिवारी ने रुस में बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी (एम बी बीएस) ने कड़ी मेहनत व समर्पण से की डिग्री प्राप्त कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन कर दिया। उनके इस उपलब्धि के लिए समाज के सभी लोगों ने हार्दिक बधाई दी है। साथ ही साथ माता पिता का नाम रोशन किया। डॉ नितिश तिवारी का पुरा परिवार मुल रूप से दिल्ली में रहता है परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल है। परिवार वालों का आशीर्वाद हमेशा नितिश के साथ रहा, वही बड़े पापा बिजेन्द्र तिवारी का सपना साकार हुआ। डॉ नितिश के पापा भारत पेट्रोलियम के ठेकेदार है, बालेन्द्र तिवारी और बड़े चाचा भूपेन्द्र तिवारी छोटे चाचा एडवोकेट सतेन्द्र तिवारी, दादी फूलकुमारी,

हुए उज्वल भविष्य की कामना की है। परिवार के सभी सदस्यों ने की गाइड लाइन पर बच्चों की पढाई का मुख्य उद्देश्य साकार हुआ है और सतेन्द्र के नेतृत्व का असर पूरे परिवार पर पड़ा जिसके कारण शिक्षा जगत में बच्चे ऊंचे पायदान पर नाम रोशन किया। वहीं नितिश तीसरे पुत्र एम बी बीएस की डिग्री हासिल किये हैं, और नितिश के ननिहाल में भी खुशी का माहौल चल रहा है। डॉ नितिश के नाना पंडित विश्वनाथ तिवारी पूर्व जिलामहामंत्री भाजपा के रह चुके हैं, आज उनके घर पर लोगों ने इस शुभ अवसर पर आकर आशीर्वाद और शुभ कामनाएं दे रहे हैं। पंडित विश्वनाथ का कहना है कि नितिश बचपन से ही कुशल और मेहनती बच्चा था। ननिहाल में उपस्थित लोग खुशी जाहिर कर बधाई देते हुए बड़े मामा भुपनारायण तिवारी दूसरे मामा ईशनारायण तिवारी, तीसरे मामा राजेश तिवारी जो कि जिलापंचायत वार्ड क्रमांक 20 के भावी उम्मीदवार हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉ नितिश के छोटे मामा आशुतोष तिवारी जो की समाज में एक अलग पहचान बनाए हैं और मुम्बई के उप नगर नालासोपारा से लोग नितिश को अनेक अनेक बधाई और शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वहीं दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र के उपसंपादक प्रेम चंद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम चौबे, आनंद कुमार मिश्रा, जगदीश तिवारी, राजेश वर्मा ने भी हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

## एफआरएनडी प्लेटफॉर्म से इलकिया को मिली उम्मीद तथा आत्मनिर्भर बनने का जरिया



मुंबई। कुछ कहानियां यह विश्वास दिलाती हैं कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, एक छोटा-सा मौका सब कुछ बदल सकता है। 28 वर्षीय इलकिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भावनात्मक सहारे, अपनापन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की उनकी तलाश को नई दिशा तब मिली, जब उन्होंने इंटरैक्ट ग्रुप के भारत के अग्रणी वॉयस-फ्रंट सोशल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म एफआरएनडी के बारे में जाना। इलकिया स्वभाव से बेहद संकोची थीं। लोगों से खुलकर बात करना उनके लिए आसान नहीं था, खासकर पुरुषों से। बार-बार अपनी

को खोने के बाद किसी पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे ही एक दौर में सोशल मीडिया पर उनकी नजर एफआरएनडी के बारे में एक वीडियो पर पड़ी। उन्हें लगा कि शायद यहाँ कोई ऐसा सुरक्षित मंच मिल जाए, जहाँ कोई उन्हें परखे बिना उनकी बात सुने और वे बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकें। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फैसला किया। इसी प्लेटफॉर्म पर इलकिया की पहचान एक ऐसे व्यक्ति से हुई, जिसके जीवन में भी दर्द और अकेलापन कम नहीं था। उसने भी अपनी मां को खोया था और धीरे-धीरे जिंदगी से निराशा हो चुका था। काम ही उसकी दुनिया बन गया था। उसके लिए जिंदगी अब बस गुजर रही थी, जी नहीं जा रही थी। देर रात तक चलने वाली बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो दोनों ने एक-दूसरे के दुर्द, संघर्ष और भावनाओं को करीब से समझना शुरू किया। धीरे-धीरे यह रिश्ता और मजबूत होता गया। सहानुभूति से शुरू हुई यह पहचान दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। इसी साल दोनों विवाह बंधन में बंध गए। इलकिया के लिए एफआरएनडी सिर्फ नए लोगों से मिलने का मंच नहीं बना, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का जरिया भी साबित हुआ। प्लेटफॉर्म से हुई आय की मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आज वे एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हैं। कभी खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने वाली इलकिया आज एक नई जिंदगी जी रही हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भरोसे, प्यार और दूसरी शुरुआत का सफर है।

## पद्मश्री डॉ. लालजी सिंह की 79वीं जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि, वैज्ञानिक योगदान को किया गया नमन



सिकरारा, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय (वीएचसी) के पूर्व कुलपति पद्मश्री डॉ. लालजी सिंह की 79वीं जयंती रविवार को उनके पैतृक गांव कलवारी स्थित डॉ. लालजी सिंह रिसर्च सेंटर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, शिक्षाविद, विद्यार्थी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने डॉ. लालजी सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके अद्वितीय योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. लालजी सिंह ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से न केवल भारत को वैज्ञानिक पहचान

दिलाई, बल्कि अपराध अनुसंधान, न्याय प्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम का आयोजन उनके भतीजे एवं संस्थान के प्रबंध निदेशक आशीष सिंह की देखरेख में किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले डॉ. लालजी सिंह युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प ली लिया गया। इस मौके पर प्राचार्य अजय कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लल्लन उपाध्याय, शरद सिंह (प्रधानाचार्य), सुदीर्घ सिंह (प्रधान प्रतिनिधि), आकाश मिश्र, डॉ. शोभनाथ यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

## बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही: अहमद खां मंडी में खुले बॉक्स से सांड को लगा करंट, तड़प-तड़प कर हुआ गंभीर घायल



जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर क्षेत्र के अहमद खां मंडी इलाके में रविवार को बिजली विभाग की एक और गंभीर लापरवाही सामने आई। यहाँ सड़क किनारे लगे बिजली के एक खुले जंक्शन बॉक्स में अचानक करंट उतर आया। इसकी चपेट में आने से एक सांड गंभीर रूप से घायल हो गया। करंट लगते ही सांड बीच सड़क पर तड़पने लगा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची जान सांड को तड़पता देख आस-बाँस से दूर किया। स्थानीय नागरिकों की इसी तत्परता के कारण सांड की जान बच सकी, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद से घायल सांड का इलाज कराया जा रहा है। पिछले साल हुई थीं तीन मौतें, फिर भी नहीं ली सीख स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पिछले साल भी नगर क्षेत्र में करंट लगने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस समय

प्रशासन और बिजली विभाग ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि सभी खुले तारों और बॉक्स को ठीक किया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि विभाग आज भी कुंभकर्णी नौद सोया हुआ है। बरसात में और भयावह हो जाती है स्थिति मौसम बदलते ही और बरसात की शुरूआत होते ही शहर की स्थिति बेहद डरावनी हो जाती है। अहमद खां मंडी समेत नगर के कई इलाकों में जगह-जगह बिजली के बॉक्स खुले पड़े हैं। कई पोल (खंभों) में भी करंट उतर रहा है। बारिश के मौसम में पानी जमा होने के कारण यह खुले बॉक्स और पोल चलते-फिरते 'डेथ ट्रैप' (मौत का जाल) बन चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन खुले बॉक्सों को बंद नहीं किया गया और जर्जर तारों को ठीक नहीं किया गया, तो वे सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।

## शिवपुर बाईपास पर स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, चालक वाहन समेत फरार

मडियाहू, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर तिराहे पर रविवार को स्कॉर्पियो और बाइक की भिड़त में एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार बरसटी थाना क्षेत्र के सराय विक्रम गांव निवासी 26 वर्षीय महताब अंसारी मडियाहू के भंडरिया टोला स्थित अपने ननिहाल आए हुए थे। रविवार को वह बाइक से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह शिवपुर बाईपास तिराहे पर पहुंचे, तेज रफतार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महताब सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मडियाहू ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफतार पिकअप ने ली दो जिगरी दोस्तों की जान, गांवों में छाया मातम

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। बड़ागांव थाना क्षेत्र के बड़ागांवबड़कपसेटी बाइपास मार्ग स्थित गजापुर के पास रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफतार प्याज लदी पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, शेरवानीपुर गांव निवासी सतीश (24) और पतेर गांव निवासी मूलचंद (25) गहरे दोस्त थे। दोनों रविवार सुबह एक ही बाइक से पेट्रोल भरवाने के लिए निकले थे। जैसे ही उनकी बाइक गजापुर पेट्रोल पंप के पास मुड़ी, सामने से आ रही तेज रफतार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पिकअप में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वाहन को पकड़ लिया और चालक इंद्रजीत वर्मा, निवासी अमसवालपुर (थाना फूलपुर), को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के अनुसार, दोनों युवक टेट हाउस में काम करते थे और घर की जिम्मेदारियों में मदद करते थे। मूलचंद विवाहित था और एक वर्ष के पुत्र का पिता था, जबकि सतीश अविवाहित था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था। यह दर्दनाक हादसा फिर एक बार तेज रफतार और लापरवाही से होने वाले सड़क हादसों की गंभीरता को उजागर करता है।

## 5वीं-8वीं की मान्यता पर धड़ल्ले से चल रही 10वीं-12वीं की कक्षाएं, शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। क्षेत्र के कई निजी विद्यालय पांचवीं अथवा आठवीं तक की मान्यता होने के बावजूद धड़ल्ले से हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। आरोप है कि ऐसे विद्यालय बच्चों और अभिभावकों को गुमराह कर प्रवेश ले रहे हैं तथा उनसे मोटी फीस वसूल रहे हैं। सूचों के अनुसार, क्षेत्र में कई विद्यालय स्वयं की यूपी बोर्ड अथवा सीबीएसई पैटर्न का बताकर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कराने का दावा कर रहे हैं, जबकि उनके पास संबंधित कक्षाओं के संचालन की आवश्यक मान्यता नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ विद्यालयों के भवन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक अभिलेख भी मानकों के अनुरूप नहीं बताए जा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय संचालक आकर्षक प्रचार-प्रसार और बड़े-बड़े दावे कर बच्चों का प्रवेश तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। यदि समय रहते ऐसे विद्यालयों की जांच नहीं हुई तो हजारों विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि वर्षों से इस तरह के विद्यालय खुलेआम

CMO Reg. RME. 2341801

# अहमदी मेमोरियल

## शिफा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

 <p><b>डॉ मोहम्मद अकमल</b> (फिजिशियन) पता - मानीकला, जौनपुर</p>	<p><b>डॉ. अरू फेमल</b> MBBS, Ortho PGDS हृत्पी और रोग विशेषज्ञ कमरे 2 कोठे में काम 4 कोठे तक (एम्बुलेंस)</p>	<p><b>डॉ मोहम्मद चांद बागवान</b> MBBS, DNB, MD (Lucknow) यूर, चेरट रोग हृदय रोग विशेषज्ञ कमरे- सुबह 9 बजे से 11 बजे तक (एम्बुलेंस)</p>	<p><b>डॉ. यूसीरा अली</b> MBBS, MS (Job &amp; Gyna Surgeon) सी रोड सामान्य चिकित्सा (Infectiology) कमरे- सुबह 9 बजे से 11 बजे तक (एम्बुलेंस)</p>
<p><b>डॉ सुनील कुमार दुबे</b> MBBS, MS (Laparoscopic Surgeon) on call</p>	<p><b>डॉ एम के वर्मा</b> P.G.D.C. (Delhi) (सी रोड चिकित्सा) कमरे- 11 कोठे तक (एम्बुलेंस)</p>	<p><b>डॉ मोहम्मद अब्दुल्लाह</b> (सी रोड चिकित्सा) कमरे- सुबह 9 बजे से 11 बजे तक (एम्बुलेंस, एम्बुलेंस)</p>	<p><b>डॉ सना अब्दुल्लाह</b> (सी रोड चिकित्सा) कमरे- सुबह 9 बजे से 11 बजे तक (एम्बुलेंस, एम्बुलेंस)</p>

डिजिटल एक्स-रे, कम्प्यूटराइज्ड पैथोलॉजी, E.C.G., हृदय रोग विशेषज्ञ, चेरट रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दन्त चिकित्सक फिजियोथेरापी, डिलेवरी (नार्मल, सिजेरियन), दूरबीन विधि से पिताशय में पथरी, अपेंडिसिटाइट, बच्चीनी, हाइड्रोसील का ऑपरेशन भर्ती की सुविधा।

पता - मानीकला, जौनपुर | 9451610571, 7380850571



# ए. एम. बजाज

काउंसिलिंग की। समझाइश और संवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। काफी देर चली बातचीत के बाद दंपती ने आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया और सुलह समझौते पर सहमति जताई। मिशन शक्ति केंद्र की इस पहल से एक टूटता हुआ परिवार पुनः एकजुट हो गया और सामाजिक स्तर पर सकारात्मक संदेश गया।